

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 972
जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

नोटरी पोर्टल में डिजिटलीकरण

972. श्री विजय बघेल :
श्रीमती कमलजीत सहरावत :
श्री भोजराज नाग :
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री नलिन सोरेन :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
श्री मनोज तिवारी :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्री शिवमंगल सिंह तोमर :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :
श्री जुगल किशोर :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) समर्पित नोटरी पोर्टल के माध्यम से कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और इसने नोटरी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत प्रक्रियाओं को किस प्रकार सरल और सुव्यवस्थित किया है;
(ख) उक्त पोर्टल के माध्यम में जारी किए गए डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित प्रैक्टिस प्रमाणपत्रों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) दस्तावेज सत्यापन और नवीनीकरण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार का भविष्य में उक्त पोर्टल के दायरे का विस्तार करने के लिए नए मॉड्यूल या कार्यात्मकताएं लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (घ) : सरकार ने नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में नोटरी पोर्टल लॉन्च

किया है। इसका उद्देश्य नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता का सत्यापन, नोटरी के रूप में व्यवसाय के डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जारी करने, व्यवसाय के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण, व्यवसाय के क्षेत्र में बदलाव, वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करना है। नोटरी पोर्टल एक फेसलेस, पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल प्रणाली प्रदान करता है। वर्तमान में, केवल दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता और नव नियुक्त नोटरियों को डिजिटली हस्ताक्षरित व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मॉड्यूल लाइव है। नोटरी पोर्टल लॉन्च होने से पहले, नोटरी को व्यवसाय प्रमाणपत्र भौतिक रूप से जारी किया जाता था। नोटरी पोर्टल के माध्यम से 30.11.2025 तक, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नवनियुक्त नोटरियों को 35,000 से अधिक डिजिटल हस्ताक्षरित व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
